GEO IAS

It's about quality

29 June 2024

GEO

Daily

Daily Current Affairs

GEO IAS

SOURCES

THE HINDU | The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE | pib | AIR | live mint | THE FINANCIAL EXPRESS | ET ECONOMIC TIMES.COM

Date: 29 June 2024

Important News Articles

1. DAY-NRLM ने 'लखपति दीदी बनाने' पर कार्यशाला का आयोजन किया
2. गर्भवती महिलाओं में गर्भावधि मधुमेह की जांच HbA1c से की जानी चाहिए- द हिंदू
3. भारत ने FATF मूल्यांकन में 'उत्कृष्ट परिणाम' हासिल किया - द हिंदू
4. भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी रिपोर्ट की आलोचना की - द हिंदू
5. भारतीय विदेश मंत्री SCO शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे - इंडियन एक्सप्रेस
6. रूस ने काला सागर पर अमेरिकी ड्रोन के खिलाफ 'जवाबी' की चेतावनी दी - द हिंदू
7. दिल्ली की बारहमासी जलभराव समस्या से संबंधित मामला -इंडियन एक्सप्रेस

Editorials, Gists and Explainers

8. दिल्ली हवाई अड्डे की छत ढहने की घटना: भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थिति - इंडियन एक्सप्रेस
9. फॉक्सकॉन रोजगार विवाद: कंपनी ने विवाहित महिलाओं को नौकरी पर नहीं रखा- इंडियन एक्सप्रेस
10. GST परिषद बैठक: जीएसटी परिषद को व्यापक सुधारों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए- द हिंदू

Quick Look

1. अर्थोपाय अग्रिम (वेज एंड मीन्स एडवांस/WMA)
2. शंघाई सहयोग संगठन
3. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)
4. आठ कोर उद्योग सूचकांक (ICI)
5. इंजीन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर

महत्वपूर्ण समाचार लेख

सामान्य अध्ययन I

1. DAY-NRLM ने 'लखपति दीदी बनाने' पर कार्यशाला का आयोजन किया

प्रीलिम्स टेकअवे
- SHG
- DAY-NRLM

प्रासंगिकता: महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपाय।

समाचार:
- प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की दिशा में अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए,
- ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने आज महिला स्वयं सहायता समूहों को सेवा क्षेत्र के उद्यमों में एकीकृत करने: लखपति दीदी बनाने पर एक राष्ट्रीय हितधारक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया।

मुख्य बिंदु:
- यह मिशन, प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुसार लखपति दीदियों के लिए प्रयास कर रहा है तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों की संभावनाओं की खोज और एकीकरण करते हुए लखपति पहल को मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा है।
- इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि सेवा क्षेत्र आज सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50%, नौकरियों में 31% का योगदान देता है और इसलिए इस पर खुले दिमाग से चर्चा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि SHG समुदाय की व्यापक भागीदारी के लिए उनके आर्थिक उत्थान और उन्हें लखपति दीदी बनने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह की उप-योजना शुरू की जा सकती है।
- प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2023 को लखपति दीदीयों को बनाने की घोषणा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और इसके राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन इसे साकार करने के लिए प्रेरित करते हैं।
- प्रधानमंत्री के लखपति दीदीयों के महत्वाकांक्षी सपने को साकार करने के लिए अभिसरण महत्वपूर्ण है और मंत्रालय अपने साझेदारों के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूह दीदियों को लखपति दीदीयों के रूप में आर्थिक रूप से परिवर्तित करने में मदद करने के लिए हर संभव अवसर का लाभ उठाएगा।
- कार्यशाला का आयोजन वर्तमान परिदृश्य को समझने के उद्देश्य से किया गया था - सेवा क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूहों के सामने आने वाले अवसर, क्षमता और चुनौतियाँ, महिला स्वयं सहायता समूहों को सेवा उद्यमों में एकीकृत करने के सर्वोत्तम तरीकों और सफल मॉडलों की पहचान करना और विभिन्न हितधारकों के सहयोग से अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के सफल एकीकरण के लिए आगे की राह और रणनीति विकसित करना।
- प्रतिभागियों में ग्यारह मंत्रालयों, दस राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और अन्य हितधारकों, सेक्टर कौशल परिषद, राष्ट्रीय संसाधन संगठनों और तकनीकी सहायता एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल थे।
- कार्यशाला में प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी के साथ विभिन्न विचारों और विचारों पर खुली चर्चा हुई।

सामान्य अध्ययन II

2. गर्भवती महिलाओं में गर्भावधि मधुमेह की जांच HbA1c से की जानी चाहिए- द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- HbA1c
- गर्भावधि मधुमेह

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

समाचार:
- भारत, लंदन और अफ्रीका के शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि ओरल ग्लूकोस टॉलरेंस टेस्ट्स (OGTT) के स्थान पर HbA1c परीक्षण किया जाना चाहिए।

मुख्य बिंदु:
- उन्होंने सिफारिश की है कि इसे गर्भावस्था के आरंभिक चरण में, पहली तिमाही के दौरान ही दिया जाना चाहिए।

- द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी में प्रकाशित एक शोधपत्र में, लेखकों ने तर्क दिया कि HbA1c गर्भावधि मधुमेह के लिए एक सरल स्क्रीनिंग परीक्षण प्रदान करता है, जिससे सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों को प्रारंभिक हस्तक्षेप प्राप्त करने की अनुमति मिलती है और OGTT की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है।
- यह प्रस्ताव भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुमान है कि गर्भावधि मधुमेह के 90% से अधिक मामले निम्न-आय और मध्यम-आय वाले देशों में होते हैं।
- वर्तमान में, दिशा-निर्देश अनुशंसा करते हैं कि माताएँ उपवास के समय OGTT लें, जो कि 75 ग्राम का एक केंद्रित मौखिक घोल है, और फिर 24 से 28-सप्ताह के चरण में अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए दो से तीन घंटे प्रतीक्षा करें।
- इससे अनेक चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, विशेषकर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों और पहुंच से दूर क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की जांच करने में।
- अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि भारत में, 4.9 का HbA1c परिणाम मधुमेह को खारिज करता है, जबकि 5.4 या उससे अधिक स्कोर वाली महिलाओं को गर्भावधि मधुमेह के लिए 'अस्वीकार' किया जा सकता है।
- यदि जोखिम स्कोर उन्हें सबसे कम जोखिम वाले समूह में वर्गीकृत करता है, तो उन्हें OGTT नहीं करवाना पड़ेगा, केवल इन दो मूल्यों के बीच के मध्यवर्ती समूह में रहने वालों को अधिक जटिल परीक्षण करवाना होगा।
- HbA1c परीक्षण के लाभ: यह गर्भावस्था के आरंभ में ही उच्च जोखिम वाले समूह की पहचान करने की क्षमता प्रदान करता है, तथा आहार और व्यायाम में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है।
    - ऐसे आंकड़े मौजूद हैं कि शीघ्र हस्तक्षेप से गर्भावधि मधुमेह के विकास को रोकने में मदद मिलती है।

3. भारत ने FATF मूल्यांकन में 'उत्कृष्ट परिणाम' हासिल किया - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- FATF

प्रासंगिकता: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, एजेंसियां और मंच - उनकी संरचना, अधिदेश।

समाचार:
- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए पारस्परिक मूल्यांकन में भारत ने उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए हैं।

मुख्य बिंदु:
- सिंगापुर में आयोजित FATF प्लेनरी में अपनाई गई भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट में भारत को "नियमित अनुवर्ती" श्रेणी में रखा गया है, यह अंतर केवल चार अन्य G-20 देशों द्वारा साझा किया गया है।
- यह मनी लॉन्ड्रिंग (ML) और आतंकवादी वित्तपोषण (TF) से निपटने के लिए देश के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- FATF ने एक बयान में कहा कि प्लेनरी ने निष्कर्ष निकाला है कि भारत अपनी आवश्यकताओं के साथ तकनीकी अनुपालन के उच्च स्तर पर पहुंच गया है।
- देश की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML), आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (CFT), और काउंटर-प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग (CPF) व्यवस्था अच्छे परिणाम प्राप्त कर रही है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बुनियादी और लाभकारी स्वामित्व जानकारी तक पहुंच, वित्तीय खुफिया जानकारी का उपयोग और अपराधियों को उनकी संपत्ति से वंचित करना शामिल है।
- हालांकि, FATF ने पाया कि कुछ गैर-वित्तीय क्षेत्रों में निवारक उपायों के पर्यवेक्षण और कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए सुधार की आवश्यकता थी।
- अन्य बातों के अलावा, FATF ने भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और संगठित अपराध से होने वाली आय की लूट सहित ML/TF से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के मुद्दे पर भारत द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता दी है, और ML/TF जोखिमों को कम करने के लिए नकदी आधारित अर्थव्यवस्था से डिजिटल अर्थव्यवस्था में संक्रमण के लिए भारत द्वारा लागू किए गए प्रभावी उपायों को भी मान्यता दी है।

4. भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी रिपोर्ट की आलोचना की - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- समान नागरिक संहिता

प्रासंगिकता: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, एजेंसियां और मंच- उनकी संरचना, अधिदेश।

समाचार:
- भारत ने हाल ही में वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट को "गहरा पक्षपातपूर्ण" बताया और कहा कि यह "मुद्दों का एकतरफा प्रक्षेपण" दर्शाता है।

मुख्य बिंदु

GEO IAS It's about quality

- भारत में हम धर्मांतरण विरोधी कानूनों, घृणास्पद भाषणों, अल्पसंख्यक समुदायों के घरों और पूजा स्थलों को ध्वस्त करने की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि देख रहे हैं।
- साथ ही, दुनिया भर में लोग धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं।"
- भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को समर्पित लगभग 69 पृष्ठों की रिपोर्ट में कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बहुसंख्यक समूहों के बीच स्पष्ट मिलीभगत पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है और समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए अभियान के साथ-साथ भारत में "हिंदू राष्ट्र" बनाने के अभियान जैसे कई कारकों को चिह्नित किया गया है।
- आलोचना का जवाब देते हुए भारत ने अमेरिका में कानून और व्यवस्था की स्थिति का मुद्दा उठाया तथा भारतीयों और अन्य रंगीन समुदायों के खिलाफ नस्लभेद से प्रेरित व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों को उजागर किया।
- वर्ष 2023 में, भारत ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका में घृणा अपराधों, भारतीय नागरिकों और अन्य अल्पसंख्यकों पर नस्लीय हमलों, तोड़फोड़ और पूजा स्थलों को निशाना बनाने के कई मामलों को उठाया है
- उदाहरण के लिए, भारत में ईसाई समुदायों ने बताया कि स्थानीय पुलिस ने धर्मांतरण गतिविधियों के आरोप में पूजा सेवाओं को बाधित करने वाली भीड़ की सहायता की या जब भीड़ ने उन पर हमला किया तो वे मूकदर्शक बनी रहीं और फिर पीड़ितों को धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।"

5. भारतीय विदेश मंत्री SCO शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे - इंडियन एक्सप्रेस

प्रीलिम्स टेकअवे
- शंघाई सहयोग संगठन

प्रासंगिकता: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, एजेंसियां और मंच - उनकी संरचना, अधिदेश।

समाचार:
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे।

मुख्य बिंदु:
- विदेश मंत्री एस जयशंकर कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे
- शिखर सम्मेलन 3-4 जुलाई को अस्ताना में होगा। कजाकिस्तान ने SCO की अध्यक्षता भारत से ली है, जो पिछले साल इसका अध्यक्ष था।
    - भारत जुलाई 2023 में SCO शिखर सम्मेलन की वर्चुअल मेजबानी करेगा।
- पिछले साल वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान जयशंकर ने तत्कालीन पाकिस्तान विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में आतंकवाद पर चिंता व्यक्त की थी।
- प्रधानमंत्री के रूप में अपने पिछले 10 वर्षों के दौरान, मोदी ने पांच SCO शिखर सम्मेलनों में भाग लिया है जो कोविड-19 महामारी से पहले आयोजित किए गए थे।
- भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान से मिलकर बना SCO एक प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा समूह माना जाता है।
- कजाकिस्तान द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाग लेने की उम्मीद है।

6. रूस ने काला सागर पर अमेरिकी ड्रोन के खिलाफ 'जवाबी' की चेतावनी दी - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- NTO
- काला सागर

प्रासंगिकता: विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर प्रभाव।

समाचार:
- रूस के रक्षा मंत्री ने अधिकारियों को काला सागर के ऊपर अमेरिकी ड्रोन उड़ानों का "जवाब" तैयार करने का आदेश दिया
- इसमें स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि मास्को अमेरिकी टोही विमानों को रोकने के लिए बलपूर्वक कार्रवाई कर सकता है।

मुख्य बिंदु
- रूसी रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में काला सागर के ऊपर अमेरिकी ड्रोन की "बढ़ी हुई तीव्रता" पर ध्यान दिया
    - मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "यह यूक्रेन में संघर्ष में कीव शासन के पक्ष में अमेरिका और अन्य नाटो देशों की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।"

- वाशिंगटन और मॉस्को के बीच काला सागर में अमेरिकी ड्रोन को लेकर पहले भी टकराव हो चुका है।
- वर्ष 2023 की एक घटना में, एक रूसी लड़ाकू जेट ने वहां एक अमेरिकी ड्रोन को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
- इस तरह के टकराव की पुनरावृत्ति से तनाव और बढ़ सकता है।

सामान्य अध्ययन III

7. दिल्ली की बारहमासी जलभराव समस्या से संबंधित मामला -इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: आपदा और आपदा प्रबंधन।

प्रीलिम्स टेकअवे
• शहरी बाढ़

समाचार:

- दिल्ली में भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसकी वजह कई प्रशासनिक खामियां हैं।

मुख्य बिंदु:

- मानसून की पहली बारिश ने दिल्ली को गर्मी से बड़ी राहत तो दी है, लेकिन तीन घंटे की भारी बारिश ने राष्ट्रीय राजधानी को अस्त-व्यस्त कर दिया।
- ऐसा तब है जबकि लोक निर्माण विभाग ने दावा किया है कि गाद निकालने का काम 83 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
- वरिष्ठ PWD अधिकारियों और विशेषज्ञों के अनुसार, इसके प्रमुख कारण विभागों की बहुलता, समन्वय की कमी, खराब बुनियादी ढांचा, दोषपूर्ण डिजाइन और बढ़ती जनसंख्या हैं।
- एक अन्य प्रमुख कारण लंबे समय से लंबित 'ड्रेनेज मास्टर प्लान' है, जिसे कई समस्याओं के कारण अभी तक लागू नहीं किया गया है
- शहर की जल निकासी व्यवस्था में क्षमता नहीं है। यह बहुत पुरानी भी है और आबादी लगातार बढ़ रही है।
    - एक एकीकृत मास्टर प्लान की आवश्यकता है।

एडिटोरियल, जिस्ट, एक्सप्लेनेर

8. दिल्ली हवाई अड्डे की छत ढहने की घटना: भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थिति - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, हवाई अड्डे, रेलवे आदि।

प्रसंग:

- हाल ही में भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिर गया, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और छह घायल हो गए।

मुख्य बिंदु	सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता
• यह घटना भारत में सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की नाजुक स्थिति को उजागर करती है तथा ऐसी संरचनाओं की सुरक्षा और अखंडता के बारे में गंभीर सवाल उठाती है। • एक हवाई अड्डा, विशेष रूप से राजधानी शहर में, आधुनिक इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और सुरक्षा का प्रतीक है। इसे किसी त्रासदी का स्थल नहीं बनना चाहिए। • वर्ष 2008 की संरचना किसी भी मानक से पुरानी नहीं है। निजी ठेकेदारों से संबंधित मुद्दे पर, जवाबदेही और सरकारी निगरानी के बारे में सवाल बने हुए हैं। • वास्तविक चिंता यह है कि ऐसी संरचनाओं की सुरक्षा और अखंडता बनाए रखने के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट नियमित रूप से क्यों नहीं किया जा रहा है। • ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए नियमित ऑडिट और रखरखाव जाँच महत्वपूर्ण हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि उन्हें नजरअंदाज किया गया है।	• इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए गहन जांच आवश्यक है। • इन्फ्रास्ट्रक्चर में राज्य के निवेश का दृष्टिकोण केवल निर्माण के बारे में प्रतीत होता है, न कि पोषण के बारे में • ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियमन और इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की बेहतर निगरानी की तत्काल आवश्यकता है। • नियमित सुरक्षा ऑडिट आयोजित किए जाने चाहिए, निर्माण मानकों का पालन किया जाना चाहिए, तथा सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली स्पष्ट जवाबदेही व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। • गुणवत्ता नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानदंडों के पालन पर जोर दिया जाना चाहिए। नियोजन और क्रियान्वयन में कमियों को दूर करना महत्वपूर्ण है। • इन्फ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं है बल्कि इसका मतलब उन लोगों से है जो इसका इस्तेमाल करते हैं। • सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफलता एक गहरे सामाजिक मुद्दे को दर्शाती है, जहां मानव जीवन को वह प्राथमिकता नहीं दी जाती जिसका वह हकदार है। • यह घटना हमें सचेत करने वाली है कि हम अपनी नीतियों और कार्यप्रणालियों का पुनर्मूल्यांकन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि इन्फ्रास्ट्रक्चर का डिजाइन मानव जीवन और कल्याण को खतरे में न डाले।

9. फॉक्सकॉन रोजगार विवाद: कंपनी ने विवाहित महिलाओं को नौकरी पर नहीं रखा- इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
प्रसंग:

- तमिलनाडु में एप्पल आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन के असेंबली मुख्यालय की रॉयटर्स की जांच में नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताएं सामने आई हैं। विवाहित महिलाओं को गर्भावस्था, पारिवारिक प्रतिबद्धताओं और अधिक छुट्टियों के आधार पर खारिज कर दिया जाता है।

संवीक्षा	यह किसकी गलती ?
• भारत में, जहां राजनीतिक दलों ने महिलाओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और जहां प्रधानमंत्री ने लैंगिक समानता के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को बार-बार दोहराया है, वहां महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाने का कोई मतलब नहीं है। • श्रम बल भागीदारी 32.7 प्रतिशत होगी जबकि पुरुषों के लिए यह 76.8 प्रतिशत होगी। • इसमें खामियां बहुत हैं और जमीनी स्तर पर इसे लागू करने का संघर्ष, कल्पना की कमी से उत्पन्न अवरोधक प्रक्रिया में फंस गया है। • यह कल्पना की विफलता है जो विकल्पों पर विचार करने से इंकार करती है, जो कार्यस्थलों पर पुरुष और महिला दोनों कर्मचारियों के लिए लाभकारी क्रेच सुनिश्चित नहीं करती है, या महिलाओं पर असंगत देखभाल के बोझ पर विचार नहीं करती है।	• यह विफलता सिर्फ़ सरकार या राजनीतिक दलों की नहीं है। इसकी शुरुआत व्यक्तियों और परिवारों से होती है और फिर यह संगठनों और समाज से सरकारों तक पहुँच जाती है। • बहुत सी महिलाओं से कहा जाता है कि वे "भाग्यशाली" हैं कि उनके परिवार उन्हें बाहर काम करने की "अनुमति" देते हैं या उनके साथी घर के कामों में मदद करते हैं। • **सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति:** UN वीमेन और UNDESA की जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि उपाय नहीं किए गए तो महिलाओं की एक पूरी पीढ़ी पूर्वाग्रही मानदंडों से घिरी हुई, पुरुषों की तुलना में घरेलू कामकाज में असंगत समय व्यतीत करेगी। • इस वर्ष की शुरुआत में, भारत संघ एवं अन्य बनाम पूर्व लेफ्टिनेंट सेलिना जॉन मामले में , भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि विवाह के आधार पर कामकाजी महिलाओं को दंडित करने वाले नियम असंवैधानिक हैं। • भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के लिए, जो महिलाओं को बदलाव के केंद्र में रखती है, उसे अपने मूल्यांकन के मापदंडों को फिर से उन्मुख करने की आवश्यकता होगी।

10. GST परिषद बैठक: जीएसटी परिषद को व्यापक सुधारों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए- द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का जुटाव, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।
प्रसंग:

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की बैठक पिछले सप्ताह लगभग नौ महीने में पहली बार बुलाई गई थी।

मुख्य बिंदु

- कई उद्योग-विशिष्ट उपायों के अलावा, जिनमें से कुछ पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होंगे
- परिषद ने GST के पहले तीन वर्षों के लिए कर बकाया पर ब्याज और जुर्माना माफ करने का भी विकल्प चुना, बशर्ते कि उनका भुगतान मार्च 2025 तक किया जाए।
- इसके अलावा, इसने अपील दायर करने के लिए निर्धारित पूर्व-जमा राशि को कम कर दिया, जिसमें आगामी GST अपीलीय न्यायाधिकरणों के साथ दायर की जाने वाली अपीलें भी शामिल हैं।
    - और करदाताओं के लिए पिछले रिटर्न में त्रुटियों या चूक को सुधारने के लिए एक नया फॉर्म स्वीकृत किया।
- बारीकियों से परे, परिषद ने मुनाफाखोरी विरोधी धारा को समाप्त करने पर भी हस्ताक्षर किए, जिसके तहत कंपनियों को कर कटौती से होने वाले लाभ को ग्राहकों तक पहुंचाना अनिवार्य था।
    - और पूरे भारत में चरणबद्ध तरीके से सभी GST पंजीकरणों के लिए बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य किया
- यह ताज़ा करने वाली बात है कि परिषद ने बहु-दर GST संरचना को युक्तिसंगत बनाने के लिए वर्ष 2021 की योजना का जायजा लेने की भी योजना बनाई है, जो कुछ समय से ठंडे बस्ते में है, जब वह अगली बैठक करेगी।
- सर्वोच्च GST निकाय को न केवल GST दर सुधारों को पुनर्जीवित और तेज करना चाहिए, बल्कि कर दरों में फेरबदल करते हुए पेट्रोलियम और बिजली जैसी बहिष्कृत वस्तुओं को GST के दायरे में लाने के लिए एक रोडमैप भी शामिल करना चाहिए।

फैक्ट फटाफट

1. अर्थोपाय अग्रिम (वेज एंड मीन्स एडवांस/WMA)

- यह केंद्र और राज्यों दोनों के लिए RBI से उधार लेने की सुविधा है।
- ये उधारी विशुद्ध रूप से उनकी प्राप्तियों और व्ययों के नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन को दूर करने में मदद करने के लिए हैं।
- RBI अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) केंद्रीय बैंक को केंद्र और राज्य सरकारों को उधार देने के लिए अधिकृत करती है, बशर्ते कि अग्रिम भुगतान की तारीख से तीन महीने के भीतर उन्हें चुकाया जा सके।
- WMA पर ब्याज दर RBI की रेपो दर है, जो मूल रूप से वह दर है जिस पर वह बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है।

2. शंघाई सहयोग संगठन

- शंघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी
- वर्ष 2002 में, सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक में शंघाई सहयोग संगठन के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए, जो 19 सितंबर, 2003 को लागू हुआ।
- यह एक क़ानून है जो संगठन के लक्ष्यों, सिद्धांतों, संरचना और गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्रों को निर्धारित करता है।
- SCO का लक्ष्य सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास, मित्रता और अच्छे पड़ोसी संबंधों को मजबूत करना है
- SCO की आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी हैं।
- SCO में वर्तमान में 9 सदस्य हैं, भारत भी SCO का सदस्य है।

3. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)

- FATF एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जिसका गठन 1989 में ग्रुप ऑफ सेवन (G7) के सदस्य देशों द्वारा किया गया था जिसका उद्देश्य धन शोधन और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के मामलों को रोकना है।
- इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है।
- FATF में 37 सदस्य क्षेत्राधिकार और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं, जिनमें यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) शामिल हैं।
    - भारत FATF का सदस्य है

- इसका उद्देश्य धन शोधन और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय विधायी और नियामक सुधारों को लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति उत्पन्न करना है।
- FATF मानकों का अनुपालन न करने से प्रतिष्ठा को नुकसान, वित्तीय अलगाव, तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से जांच बढ़ सकती है।

4. आठ कोर उद्योग सूचकांक (ICI)

- आठ कोर उद्योगों का सूचकांक (ICI) हर महीने तैयार किया जाता है और आर्थिक सलाहकार कार्यालय (OEA), उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।
- ICI आठ प्रमुख उद्योगों अर्थात सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और इस्पात के उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल वस्तुओं के भार का 40.27 प्रतिशत हिस्सा आठ प्रमुख उद्योगों का है।
- आठ प्रमुख उद्योगों का वर्तमान भार इस प्रकार है: पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद (28.04%)> बिजली (19.85%)> इस्पात (17.92%)> कोयला (10.33%)> कच्चा तेल (8.98%)> प्राकृतिक गैस (6.88%)> सीमेंट (5.37%)> उर्वरक (2.63%)।
- ICI की वर्तमान श्रृंखला में आधार वर्ष 2011-12 है।

5. इंजीन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर

- इंजीन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर एक छोटा रोबोट हेलीकॉप्टर है जो नासा के मार्स 2020 मिशन का हिस्सा है, जिसमें पर्सिवियरेंस रोवर भी शामिल है।
- यह किसी अन्य ग्रह पर संचालित, नियंत्रित उड़ान का प्रयास करने वाला पहला विमान है।
- इंजीन्यूटी का प्राथमिक मिशन मंगल ग्रह के पतले वायुमंडल में उड़ान की व्यवहार्यता का प्रदर्शन करना और लाल ग्रह के भविष्य के हवाई अन्वेषण के लिए डेटा एकत्र करना है।

GEO IAS
It's about quality

प्रीलिम्स ट्रैक

Q.1 स्वयं सहायता समूहों (SHG) और भारत में महिला सशक्तीकरण पर उनके प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ग्रामीण महिलाओं को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने में स्वयं सहायता समूह एक प्रमुख साधन रहे हैं, जिससे उनके वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का लक्ष्य 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुंचना और उन्हें स्थायी आजीविका से जोड़ना है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

Q2. गर्भावधि मधुमेह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें

1. गर्भावधि मधुमेह से पीड़ित महिलाओं को आगे चलकर टाइप 2 मधुमेह होने का अधिक खतरा रहता है।
2. गर्भावधि मधुमेह का निदान केवल गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में ही किया जा सकता है।
3. अनुमान है कि गर्भावधि मधुमेह के 90% से अधिक मामले उच्च आय वाले देशों में होते हैं

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

Q3. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें

1. FATF की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए की गई थी।
2. FATF उच्च जोखिम वाले और असहयोगी क्षेत्राधिकारों की एक सूची जारी करता है, जिसे आमतौर पर "ब्लैकलिस्ट" और "ग्रेलिस्ट" के नाम से जाना जाता है।
3. FATF की सिफारिशों का अनुपालन सभी सदस्य देशों के लिए अनिवार्य है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2
C. केवल 1 और 3
D. केवल 2 और 3

Q 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र में अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (UCC) प्रदान करने का प्रयास करेगा।
2. आपराधिक कानूनों को संहिताबद्ध कर दिया गया और वे पूरे देश के लिए समान हो गए, फिर भी व्यक्तिगत कानून विभिन्न समुदायों के लिए अलग-अलग संहिताओं द्वारा शासित होते रहे।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

A. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I का सही व्याख्या है
B. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I का सही व्याख्या नहीं है
C. कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है
D. कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है

Q5. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें

1. SCO की स्थापना 2001 में सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी।
2. भारत और पाकिस्तान 2017 में SCO के पूर्ण सदस्य बन गए।
3. SCO की आधिकारिक भाषाएँ चीनी और रूसी हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

Q6. नॉर्ड स्ट्रीम - 2 पाइपलाइन जो हाल ही में खबरों में थी, किससे संबंधित है?

1. उत्तरी सागर
2. बाल्टिक सागर
3. आज़ोव सागर
4. फिनलैंड की खाड़ी

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. केवल 2 और 4

Q 7. भारत में नगर पालिकाओं और शहरी प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं की स्थापना का प्रावधान करता है।
2. संविधान का अनुच्छेद 243Q नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है।
3. राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों की तैयारी तथा नगर पालिकाओं के सभी चुनावों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. 2, और 3 केवल
D. 1, 2, और 3

Q 8. मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार करें:

1. इसमें भारतीय समुद्री क्षेत्र के सभी पहलुओं को कवर करने वाली 150 से अधिक पहल शामिल हैं।
2. यह जलमार्ग संपर्क परिवहन ग्रिड का निर्माण करेगा, जो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ संपर्क विकसित करेगा।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

Q 9. भारतीय संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लोकसभा में महिला सदस्यों का प्रतिशत कभी भी 15% से अधिक नहीं रहा है।
2. महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है।
3. सभी दक्षिण एशियाई देशों के बीच भारत की संसद में महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

Q 10. GST परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह अनुच्छेद 279B के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है।
2. GST परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं तथा अन्य सदस्य केन्द्रीय राजस्व या वित्त राज्य मंत्री और सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

प्रीलिम्स ट्रैक उत्तर

उत्तर : 1 विकल्प C सही है

व्याख्या

- स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण महिलाओं को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने में सहायक रहे हैं, जिससे उनका वित्तीय समावेशन बढ़ा है। **कथन 1 सही है।**
- NRLM का लक्ष्य 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुंचना और उन्हें स्थायी आजीविका प्रदान करना है। **कथन 2 सही है** ।

उत्तर : 2 विकल्प A सही है

व्याख्या

- गर्भावधि मधुमेह (GDM) मधुमेह का एक प्रकार है जो गर्भावस्था के दौरान होता है और आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद गायब हो जाता है।
- जिन महिलाओं GDM हुआ है, उन्हें जीवन में आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज़ होने का अधिक जोखिम होता है। **कथन 1 सही है।**
- GDM का निदान गर्भावस्था के किसी भी तिमाही के दौरान किया जा सकता है, हालाँकि इसका सबसे आम निदान नियमित स्क्रीनिंग परीक्षणों के माध्यम से दूसरी तिमाही में किया जाता है। **कथन 2 गलत है।**
- चूँकि अनुमान है कि गर्भावधि मधुमेह के 90% से अधिक मामले निम्न-आय और मध्यम-आय वाले देशों में होते हैं। **कथन 3 गलत है।**

उत्तर : 3 विकल्प B सही है.

व्याख्या:

- FATF की स्थापना G7 देशों द्वारा की गई थी, न कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा। **कथन 1 गलत है।**
- FATF उच्च जोखिम वाले और गैर-सहकारी क्षेत्राधिकारों की सूची जारी करता है, जिन्हें आमतौर पर "ब्लैकलिस्ट" और "ग्रेलिस्ट" कहा जाता है। **कथन 2 सही है।**
- FATF की सिफारिशों का अनुपालन अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसे अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाता है। जो देश अनुपालन नहीं करते हैं, उन्हें अधिक जांच और संभावित आर्थिक नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। **कथन 3 गलत है।**

उत्तर : 4 विकल्प B सही है

व्याख्या

- अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए पूरे भारत क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता (UCC) प्रदान करने का प्रयास करेगा।
- जबकि आपराधिक कानूनों को संहिताबद्ध कर दिया गया और वे पूरे देश के लिए समान हो गए, व्यक्तिगत कानून अभी भी विभिन्न समुदायों के लिए अलग-अलग संहिताओं द्वारा शासित होते हैं।

उत्तर : 5 विकल्प B सही है.

व्याख्या:

- SCO की स्थापना 2001 में मुख्य रूप से सुरक्षा चिंताओं, विशेष रूप से आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को संबोधित करने के लिए की गई थी, हालांकि आर्थिक सहयोग भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। **कथन 1 गलत है।**
- भारत और पाकिस्तान 2017 में SCO के पूर्ण सदस्य बन गए। **कथन 2 सही है।**
- SCO की आधिकारिक भाषाएँ चीनी और रूसी हैं। **कथन 3 सही है।**

उत्तर : 6 विकल्प D सही है

व्याख्या

- नॉर्ड स्ट्रीम-2 पाइपलाइन 1,200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो रूस के उस्त-लुगा से जर्मनी के ग्रीफ्सवाल्ड तक जाती है। यह बाल्टिक सागर और फिनलैंड की खाड़ी से होकर गुजरती है।
- सागर क्रीमिया के पास काला सागर में स्थित है ।
- उत्तरी सागर ब्रिटेन, नॉर्वे, डेनमार्क आदि देशों से घिरा हुआ है।

उत्तर : 7 विकल्प D सही है

व्याख्या

- 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, वास्तव में शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं की स्थापना का प्रावधान करता है। **कथन 1 सही है**
- संविधान का अनुच्छेद 243Q नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। **कथन 2 सही है**
- राज्य चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करने और नगर पालिकाओं के सभी चुनावों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। **कथन 3 सही है**

उत्तर : 8 विकल्प C सही है।

व्याख्या

- MIV 2030 में वर्ष 2030 तक कार्गो यातायात 2,570 mtpa तक पहुंचने का अनुमान है। इस विजन में 10 व्यापक विषयों की रूपरेखा दी गई है। इसमें भारतीय समुद्री क्षेत्र के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए 150 से अधिक पहल शामिल हैं। यह राष्ट्रीय समुद्री उद्देश्यों

को परिभाषित करने और उन्हें पूरा करने के प्रयास के रूप में सामने आया है। **(इसलिए कथन 1 सही है)**

- मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 जलमार्ग कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड बनाएगा, जो एक ऐसी परियोजना है जो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी विकसित करेगी। इसके अतिरिक्त, रिवराइन डेवलपमेंट फ़ाउंड (RDF) अंतर्देशीय जहाजों को वित्तपोषित करने और अंतर्देशीय जहाजों को टन भार कर योजना के कवरेज का विस्तार करने के लिए कम लागत वाली निधि का विस्तार करेगा। **(इसलिए कथन 2 सही है)**

उत्तर : 9 विकल्प A सही है

व्याख्या:

- ऐतिहासिक रूप से, लोकसभा में महिला सदस्यों का प्रतिशत 15% से कम रहा है। **कथन 1 सही है**
- सही। महिला आरक्षण विधेयक (108वां संशोधन) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव करता है। **कथन 2 सही है**
- भारत में संसद में महिलाओं का प्रतिशत सभी दक्षिण एशियाई देशों के बीच सबसे अधिक नहीं है; नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में यह प्रतिशत अधिक है। **कथन 3 गलत है**

उत्तर : 10 विकल्प D सही है।

व्याख्या :

GST परिषद

- यह वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर संघ और राज्य सरकार को सिफारिशें करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है (अनुच्छेद 279A)। **इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।**
- GST परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और अन्य सदस्य केंद्रीय राजस्व या वित्त राज्य मंत्री और सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री होते हैं। **इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।**
- इसे एक संघीय निकाय माना जाता है जहां केंद्र और राज्य दोनों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है।

GEO IAS
It's about quality

ABOUT US

GEO IAS is the best institute for civil services in India for providing top quality teaching and materials, offering you most optimum path for your success in Civil Services exam. Our aim is to provide quality training with an affordable fee structure. Our uniquely designed course make us the best institute for UPSC to crack the exam in one go. We have a dedicated team of experienced and young teachers and counsellors who make sure that every student who joins the institute, must get customized way of preparation which matches with student's learning style.
The only institute of UPSC in India which has 3 AI enabled Mobile apps. We believe in Smart way of teaching and learning. The classes are available in offline as well as in online mode. We take the help of animation so that you may visualize the lectures. Unlimited tests for prelims and mains with solution in both form (Hard copy and soft copy). We have the set of 15 lac mcqs on each topic. We provide daily news analysis, Highlighted news paper and links of important Sansad TV shows. The institute has best success rate with more than 230 students have cleared the exam. HIGHEST RATED INSTITUTE as per GOOGLE, SULEKHA and JUST DIAL and the magazine on civil services

+91-9477560001 /002/005

BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna |
HEAD OFFICE: 641, Ramlal Kapoor Marg,
Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

info@geoias.com

www.geoias.com